

LOK SABHA

Thursday, July 27, 1967/Sravana 5,  
1889 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P.) Ltd.**

+

\*1411. **Shri Madhu Limaye:**  
**Shri S. M. Banerjee:**  
**Dr. Ram Manohar Lohia:**  
**Shri George Fernandes:**

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 292 on the 6th April, 1967 regarding black-listing of the Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. and state:

(a) whether Government propose to lay on the Table the new or revised black-listing code and also any codes/orders in regard to reciprocal black-listing by the various Ministries and Public undertakings (through their Ministries);

(b) the stage reached in the Supreme Court appeal against the Bharat Barrel and in the writ petition against the Central Government by the firm before the Punjab High Court; and

(c) whether the injunction has since been vacated?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Baghu Ramziah): (a) A copy each of

the following papers is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1220/67].

- (i) Standardised Code for Suppliers.
- (ii) Department of Supply's Office Memorandum No. 13(7)/64-PI dated the 2nd May, 1964.
- (iii) Ministry of Petroleum & Chemicals letter No. G. 4 (102)/64 dated 21-2-66.

(b) Information regarding the stage reached in the appeal in the Supreme Court against the Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd. is being ascertained from the Government of Maharashtra. The writ petition against the Central Government before the Delhi High Court has not yet come up for hearing.

(c) No, Sir.

श्री मधु लिमये : अभी मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी है। इस प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं सप्लाय के मिनिस्टर और मेरा ब्याल है कि आयरन एंड स्टील के मिनिस्टर भी। अब तीन तीन और चार चार विभागों का यह मसला है। इस तरह के सवालों का उत्तर तो देना चाहिये प्रधान मंत्री को। नहीं तो फिर एक घंटा चला जायेगा और आप मुझ को बोध देंगे।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : आप खुद अपने को दोष दे रहे हैं।

श्री मधु लिमये : मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। तीन तीन चार चार विभागों में जो मामले सम्बन्धित हैं, जो अन्तर्विभागीय मामले हैं, उनके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रधान मंत्री को जवाब देना चाहिए।

में एप्रोप्रियेशन बिल पर भी यह मामला उठा चुका हूँ . . .

**Mr. Speaker:** The method of answering questions is already well laid down. It is being followed here.

**श्री मधु लिमये :** हाउस आफ कामन्स में करीब करीब हर दिन प्रधान मंत्री प्रश्नों का जवाब देते हैं। इन प्रश्नों का कौन जवाब देगा इसको मैं जानना चाहता हूँ। तीन तीन मंत्रालयों का इससे सम्बन्ध है। मोरारजी देसाई जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन जवाब दे सकेगा नरे प्रश्नों का ?

**श्री शिव नारायण :** अलग अलग पूछिये।

**श्री मधु लिमये :** अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

**Mr. Speaker:** The position obtaining in the House of Commons is a different matter.

**श्री मधु लिमये :** जुड़े हुए मामले हैं, इसीलिए प्रधान मंत्री का यह काम है—

**Mr. Speaker:** Whatever it is, the concerned Minister will reply.

**श्री मधु लिमये :** मंत्री महोदय ने अभी मुझ को . . .

**Mr. Speaker:** You cannot expect three Ministers to reply to the same question. Will you kindly sit down? The method of answering questions is very well laid down. The concerned Ministry consults all other Ministries before giving the answer. The hon. Member cannot expect half a dozen Ministers to answer one question.

**श्री मधु लिमये :** मंत्री महोदय ने अभी मुझ को कहा है कि हम सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं।

**Mr. Speaker:** This is the method we are following. Under the existing rules, the Minister collects information from all Ministries. If you want information from other Ministries on

any subject, you may give notice of a question to those Ministries.

**श्री मधु लिमये :** इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड कोड जो अभी मेज़ पर रखा है इसका इस्तेमाल जब किसी मंत्रालय के द्वारा—मैं केन्द्रीय सरकार की बात कर रहा हूँ—किया जाता है तो सवाल यह आता है कि क्या जो सरकारी कम्पनियाँ हैं उन पर भी यह लागू होता है ? इसके बारे में उन्होंने एक पत्र दिया है कि सरकारी कम्पनियों और सरकार के बीच में बातचीत होगी और समझौता किया जायेगा। इस पत्र में से मैं चार लाइनें पढ़ता हूँ :

"I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated.....on the above subject and to say that as you have agreed to follow the Standardised Code of Procedure for blacklisting firms....."

मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि कितनी केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों ने स्टैंडर्डाइज्ड कोड और उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है सरकार की, उसको कबूल करने का, कार्यान्वित करने का वादा किया है और उसके लिए स्वीकृति दी है ?

**Shri Raghunath Ramalal:** So far as this Ministry is concerned, every public sector undertaking under it has agreed for this reciprocal arrangement. That is all I can say at the moment.

**श्री मधु लिमये :** इसका क्या इलाज है ? यह पिछली बार हम को बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा जब किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि पब्लिक सैक्टर जो कम्पनी होती है वे तत्काल उसको लागू करें, उसके बारे में बातचीत होगी और उनकी मंजूरी प्राप्त की जायेगी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि कितनी कम्पनियों ने मान्यता दी है। मुझे क्या इसका जवाब मिलेगा ? यह प्रश्न एक सात से चल रहा है।

**Shri Raghu Ramaiah:** If the question had been put that way, we would certainly have got the information. It has been put in continuation of a starred question answered earlier in this House which related to the Indian Oil Corporation.

श्री मधु लिमये : प्रिसिपल वही है ।

**Shri Raghu Ramaiah:** What we are asked in this question is to lay on the Table the Code. That we have done. I am also giving the information so far as the public sector undertakings under this Ministry are concerned. There is no specific question about all the undertakings of the Government of India. If there was, I would have made inquiries.

श्री मधु लिमये : यह जो भारत बैरल कम्पनी है और आयरन एंड स्टील कंट्रोलर के कार्यालय के जो अफसर हैं उनके खिलाफ बम्बई के स्पेशल जज के सामने केस चला था । जज ने इन लोगों को दोषी पाया । इन लोगों ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के सामने अपील दायर की और इस अपील का जो फंसला है वह बहुत लम्बा फंसला है । उस फंसले को मैंने गौर से पढ़ा है और उसमें से एक ही पैरा में तीन चार लाइन का आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ । उससे आपको पता चलेगा कि जिस तरह इस मामले की जांच की गई, आरोप लगाये गये, चार्ज रखे गये और जिस ढंग से इस केस को चलाया गया उसमें इतनी खराबी रही कि चोर को पकड़ने में एक दिक्कत पैदा हुई । हाई कोर्ट स्वयं इसके बारे में कहती है :

“Evidence of Shankaran”—

यह आफिसर है आयरन एंड स्टील कंट्रोलर के आफिस का

“was not challenged by the prosecution as untruthful by declaring him as hostile nor was there any indication given to the accused that the prosecution wanted to challenge the

evidence of this witness of theirs as untrue. According to Mr. Jethmalani”—

यह काउन्सेल था भारत बैरल कम्पनी का

“it was not, therefore, permissible for the prosecution to urge or for the learned Judge to hold that the evidence of Shankaran was not true.”

इसमें दिक्कत यह है कि आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री के अफसर और ये कम्पनियां, इनमें आपस में कैंल्यूशन रहता है । यह कई बार साबित हो चुका है । पी० ए० सी० की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र आ चुका है । भूतलिंगम, बाम से लेकर नीचे तक मामले हैं । जब कभी ब्लैक लिस्ट करने का मामला उठता और किसी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो वे लोग तुरन्त हाई कोर्ट में जा कर इंजैक्शन ले आते हैं । बीजू पटनायक के मामले में यही हुआ, अमी चन्द प्यारे लाल के मामले में हुआ तथा और भी कई मामलों में होता है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय एक ऐसी संवैधानिक समिति नियुक्त करने के संबंध में विचार करेंगे या जो वर्तमान समितियां हैं उन समितियों के पास इस मामले को भेजेंगे ताकि संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, भ्रष्टाचार, शुद्ध शासन आदि के जितने सारे सवाल हैं उनकी रोशनी में इसके बारे में ठीक फंसला हो सके और जो रपट वह समिति दे सरकार बाद में उस रपट पर विचार करे या जो भी कुछ करना है, करे । क्या इसके लिये सरकार तैयार है ?

**Shri Raghu Ramaiah:** My hon. friend has referred to some proceedings in the Maharashtra High Court—it is now in the Supreme Court—regarding presumably some steel quota. This Ministry has nothing to do with that. That is dealt with by the Iron and Steel Ministry. If any specific question on that is to be put, I would very humbly submit that the proper forum will be the Iron and Steel Ministry or some other Ministry.

**Mr. Speaker:** Not about that. If under similar circumstances....

**श्री मधु लिमये :** डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकते हैं। मैंने जजमेंट से पढ़ा है यह कोई मामूली चीज नहीं है।

**Mr. Speaker:** That is Steel Ministry.

**श्री मधु लिमये :** कोई भी हो, यह खंडित सरकार नहीं है। इंटिग्रेटेड है, एक है, कोलक्टिव रिसर्पासिबिलिटी है। बार बार इस तरह मंत्री करेंगे ? मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सवाल को पूछता हूँ। कोर्ट से इंजैकशन आता है, इस तरह का कोल्यूशन होता है, ब्लैक लिस्ट करने का जो आर्डर है उसमें खामियां हैं या कोड में खामियां हैं तो उनके बारे में विचार करने के लिये एक संसदीय समिति बनाये और जो रपट वह दे उसको आप देखें और जो करना हो करें। इसमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये।

**The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta):** The hon. Member put a very simple question. His contention was that the prosecutor there did not declare a particular witness hostile and he read the judgment. The prosecutor in this case was the Government of Maharashtra. I am not in a position to answer on their behalf. As far as people going to the High Court or the Supreme Court is concerned.....

**श्री मधु लिमये :** इनवैस्टीगेशन तो स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट ने किया था। वह तो केन्द्र के तहत है।

**Shri Asoka Mehta:** He read out a paragraph and you heard that paragraph. The paragraph says that the prosecution should have declared a particular officer from the office of the Steel Controller to be a hostile witness and that, as he was not declared as a hostile witness, the defence counsel was able to say that certain things could not be concluded and the judge was not able to hold them res-

possible. That is what he read out. If the prosecution did not declare a particular person as a hostile witness, for that the responsibility lies on the Maharashtra Government. How am I to answer that?

The other question is that repeatedly the stay orders are taken. What committee can be appointed? This Government believes in the rule of law and we believe in not denying the legitimate rights to the aggrieved people.

**श्री मधु लिमये :** एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिये संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूल आफ ला की बात कर रहे हैं।

**Shri Asoka Mehta:** I am quietly listening to what the hon. Member is saying. He should hear patiently what I am saying.

**श्री मधु लिमये :** आप ठीक आर्युमेंट करें, तो हम सुनें।

**Shri Asoka Mehta:** He decides what the argument should be. Sir, the High Court has acquitted those people. The Maharashtra Government has gone to the Supreme Court. The matter is still before the Supreme Court. In the meantime, any denial of quota or any denial of rights to this party has been stopped by the stay order issued by the Punjab High Court. I do not know what the Government is expected to do in this. To the best of my understanding—the Deputy Prime Minister is here—this Government, because it is committed to the rule of law, is not willing to interfere with the legitimate rights of aggrieved people. My hon. friend also has not hesitated in asking for stay order over and over again. The right that he enjoys should be allowed to other citizens also in the country.

**Shri S. M. Banerjee:** This particular Question has a reference to Q. 292 of 6th April, 1967. There also, when we started putting questions, we did refer to certain action taken or not taken by some of the Departments,

the D.G.S. & D. which comes under the Supply Ministry and the Steel Ministry. In this case, our greatest anxiety is that when the firm was blacklisted, despite blacklisting order, this firm was given quota to the tune of lakhs of rupees. This is against all canons of justice; this is against the principles laid down by the D.G.S. & D. and the Supply Ministry. That is how this particular question arose.

With this background, I should like to know from the Minister whether this matter has been investigated. On April 6, 1967, my question was not answered. I said:

"It is an admitted fact. Last time, this question was asked and Mr. L. N. Mishra was replying. One of the ministers said that they had no information at that time. I want to know whether it is a fact that after the investigation, concessions were shown to this firm because Mr. Jalan had given a handsome amount to the Congress Party...."

I do not blame them; let them take it.

श्री सीताराम केसरी : यह झूठ बात है।

**Mr. Speaker:** I would only say that this is most irrelevant. Will you come to your question? Two supplementaries have taken 15 minutes. That is how the whole House is suffering.

श्री मधु लिमये : यह देश सफ़र कर रहा है। यह सभा देश की रक्षा के लिये है।

**Mr. Speaker:** One Question is taking half an hour, giving background and all that. I am not going to allow this.

श्री मधु लिमये : यह मामला दो सालसे चल रहा है।

**Shri S. M. Banerjee:** I have taken only one minute. Why are you accusing me of all this?

My question is this. I want to know whether any action has been taken against the Department concerned which showed undue leniency towards this particular firm despite the blacklisting order. May I know whether the Minister refutes that to say that it has nothing to do with the political manoeuvring?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** May I say, in general, in regard to the point raised by Shri Madhu Limaye and also Shri Banerjee, that I very much appreciate the anxiety of my hon. friends to expose whatever wrong has been done in any place, in any Department, or anywhere? Government would like to be in possession of such complaints and information. But when a Question is asked here involving several Ministries—I can certainly obtain information from the Ministries concerned but it is not possible for all Ministries to be present at the same time because different days are allotted for different Ministers. If a Minister can be present here, he can reply. May I suggest that in all such matters where my hon. friends are very anxious—we are equally anxious to find out the facts and let them know; we do not want to keep back any information from the hon. Members—if they only let us know by a letter, then the Minister concerned will certainly give them all the information? If it is not given, then, certainly they can say so and, afterwards, they can ask for further information and we will give information as soon as possible. May I assure them I will be as helpful as I can in getting information if they do not get it otherwise?

**Shri S. M. Banerjee:** I rise on a point of order.

**Mr. Speaker:** During Question Hour, there is no point of order.

**Shri S. M. Banerjee:** Kindly read the question. What the Deputy Prime Minister has said is a good sermon

to us. We accept it. But the question pertains to the reply given to Starred Question No. 292 on the 6th April, 1967, regarding black-listing of the Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co., Private Ltd. Kindly read the first part of the question put on the 6th April, 1967. Today also the question pertains to black-listing of the Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. My pertinent question is whether even after black-listing, they were given orders. That is a simple question which arises out of this. It has nothing to do with this Ministry or that Ministry. Let them answer whether they have placed the orders or not. I want to know why undue leniency was shown to them.

**Shri Raghu Ramaiah:** Today's question has a reference to Starred Question No. 292. Starred Question 292 asks as to what action has been taken by the Indian Oil Corporation in the matter of black-listing of Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. We have explained at length that except for a certain lapse during a particular period, since May 1966, no order has been given to them. Today's question refers to that question and asks for a copy of the black-listing order and certain other documents, which are laid on the Table of the House.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या यह सच है कि भारत बैरल के कंट्रेक्ट को खत्म करने के बाद आई० ओ० सी० ने हिन्द गैल्वनाइजिंग और स्टैंडर्ड ड्रमज नाम की जिन दो कम्पनियों को ड्रम और बैरल बनाने का कंट्रेक्ट दिया है, उन्होंने टेंडर में जो शर्तें मान लीं, उनके बारे में कई किस्म की बदमाशी की और इस बारे में सरकार के पास कई आवेदनपत्र आये हैं; यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ।

**Shri Raghu Ramaiah:** So far as Bharat Barrel is concerned, a complaint was received and last time I did mention to the House that we had asked the Indian Oil Corporation as to why, after black-listing, certain

orders were given. That matter is under inquiry.

As regards the other company, if he gives me notice, I will lay the necessary information on the Table of the House.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को ज़रा ठीक ढंग से समझ लें । मैंने यह पूछा है कि भारत बैरल के कंट्रेक्ट के खत्म होने के बाद हिन्द गैल्वनाइजिंग और स्टैंडर्ड ड्रमज नाम की जो दो कम्पनियाँ इस वक्त आई० ओ० सी० को ड्रम और बैरल सप्लाई कर रही हैं, क्या उनके बारे में कोई शिकायत मंत्री महोदय के पास आई है; यदि हां, तो उनके बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**Shri Raghu Ramaiah:** Offhand I cannot say because this question relates only to Bharat Barrel. Let that question be put and I shall furnish all available information. But this question does not refer to it.

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब श्री मधु लिमये ने कहा कि इस प्रश्न का सम्बन्ध अन्य मंत्रालयों से भी है, तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि यह इंडियन आयल कारपोरेशन का प्रश्न है, इसलिए मेरी मिनिस्ट्री इसका जवाब दे रही है और अन्य प्रश्नों को मुझ से न पूछा जाये, लेकिन अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह प्रश्न केवल भारत बैरल के बारे में है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इंडियन आयल कारपोरेशन का प्रश्न है, मंत्री महोदय उसके लिये जिम्मेदार हैं और इसलिये उन को सारी मालूमात सदन के सामने रखनी चाहिये ।

**Shri Asoka Mehta:** We have got to give replies very carefully. Unless the particular question is put to us in advance, we do not bring the documents. On the basis of our memory if I were to mislead the House, I would be guilty of it. This question

is about Bharat Barrel. There may be hundred other barrel companies. How am I to know all about these hundred barrel companies?

श्री जार्ज फरनेन्डोज : मैं तो सिर्फ दो कंपनियों के बारे में बोल रहा हूँ।

**Shri Ashoka Mehta:** Let him table a separate question. How can I carry all the information?

श्री जार्ज फरनेन्डोज : अध्यक्ष महोदय, यह मालूमत को छिपा रहे हैं। लाखों रुपये की चोरी हो रही है।

**C.C.A. To Government Employees in Delhi**

+

\*1412. **Shri A. B. Vajpayee:**  
**Shri N. S. Sharma:**  
**Shri Ram Singh Ayarwal:**  
**Shri Sharda Nand:**  
**Shri Brij Bhushan Lal:**

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to increase the rate of City Compensatory Allowance for Government employees in Delhi keeping in view the population of the Capital and the high cost of living; and

(b) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri K. C. Pant):**

(a) No, Sir.

(b) Under the existing criterion of population, Delhi is already one of the four 'A' Class cities enjoying the highest rates of Compensatory (City) Allowance. There is no case for considering enhancement of the existing rates of Compensatory (City) Allowance in 'A' Class cities.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर महंगाई भत्ता देने के लिए नगरों का वर्गीकरण किया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या का अनुमान जब जनसंख्या की गणना की जाती है केवल उसी समय लगाया जाता है या बीच में भी सरकार जनसंख्या का अनुमान लगाकर नगरों को जो वर्ग दिया जाना चाहिए, वह देती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह जनगणना के आधार पर ही होता है। दस साल में जनगणना की जाती है और हर दस साल के बाद उसी के आधार पर यह किया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि नागपुर, अमृतसर, इलाहाबाद और मद्रास तथा अन्य नगरों के केन्द्रीय कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई है और बड़ी हुई जनसंख्या के अनुसार उन नगरों का वर्गीकरण होना चाहिए? तो क्या मैं यह समझूँ कि उन नगरों के केन्द्रीय कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता लेने के लिए दस साल तक रुकना पड़ेगा ?

एक माननीय सदस्य : अब तो चार साल हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अब तो चार ही साल हैं, यही मैं भी कहने वाला था।

श्री ना० स्व० शर्मा : दिल्ली के रहने वाले सरकारी कर्मचारी और सब स्थानों के सरकारी कर्मचारियों के समान जीवन स्तर का उपयोग कर सकें इसके लिए क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि दिल्ली नगर प्रतिकर भत्ते का सम्बन्ध दिल्ली नगर के प्राइस इन्डेक्स से जोड़ दिया जाये जिससे प्राइस इन्डेक्स के घटाव बढ़ाव के साथ-साथ उनका प्रतिकर भत्ता भी घटता बढ़ता रहे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सुझाव है, सजेशन फार एक्शन है। वैसे दिल्ली नगर के लिये कोई अलग प्राइस इन्डेक्स नहीं है।